

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1998
05 मई, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए

नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति

1998. श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री नाना पटोले:
श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वस्त्र उद्योग के विकास के लिए कोई कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर केरल में उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिनका उन्नयन किए जाने का विचार है;

(ग) क्या वर्तमान में वस्त्र उद्योग संकट की स्थिति में है और इसके विकास को तेज करने के लिए नीति संबंधित परिवर्तन और पर्याप्त वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वस्त्र उद्योग के विकास को बेहतर बनाने और इसमें वृद्धि करने के लिए नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति (एनएनटीपी) लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एनएनटीपी के अंतर्गत 350 लाख रोजगार अवसरों का सृजन और 300 बिलियन डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) एनएनटीपी के अंतर्गत वस्त्र उद्योग में निवेश को आकर्षित करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, हां। सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी), एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस), एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना जैसी

केंद्रीय क्षेत्र की कई योजनाओं के साथ-साथ तकनीकी वस्त्र, विद्युतकरघा, रेशम, ऊन, पटसन, हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास की योजनाओं को भी क्रियान्वित करती है।

(ख): केरल सहित देशभर की वस्त्र इकाइयों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफस) के अंतर्गत सहायता के लिए वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक केरल राज्य से 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ग): जी, नहीं। वस्त्र उद्योग वर्तमान में किसी संकट का सामना नहीं कर रहा है।

(घ) से (च): नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
